सीसीपी कानून- 9वां सवांद पत्र

अंतिम सम्मेलन - ह्यू यूनिवर्सिटी, वियतनाम

जलवायु परिवर्तन कानून और नीति (सीसीपी-लॉ) परियोजना का अंतिम सम्मेलन वियतनाम के ह्यू शहर में हुआ। इस कार्यक्रम का समन्वय ह्यू विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जिसमें वियतनाम, भारत, मलेशिया, ग्रीस, यूके और स्पेन के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के १० सदस्य शामिल हुए।

७ जनवरी, २०२५ को प्रतिभागियों ने अंतिम सम्मेलन में भाग लिया।अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु संकट के बारे में संवाद को बढ़ावा देना और भावी स्नातकों और वर्तमान कानूनी पेशेवरों और पर्यावरणविदों दोनों के लिए उच्च गुणवत्ता और अभिनव शिक्षा के उच्च शिक्षा प्रावधान के महत्व पर नेटवर्किंग स्थापित करना है। सम्मेलन जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में कानूनी चिकित्सकों और पर्यावरणविदों की स्थिरता के प्रभाव को बढ़ाने पर केंद्रित है।

यूरोपीय संघ और एशिया के अग्रणी शिक्षाविद जलवायु परिवर्तन कानून में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि और प्रगति को साझा करने के लिए एक साथ आए। सी सी पी- कानून अंतिम सम्मेलन के पहले सत्र की शुरुआत प्रभावशाली प्रस्तुतियों के साथ हुई जिसने सार्थक चर्चाओं के लिए मंच तैयार किया।

- ह्यू विश्वविद्यालय की डॉ. डो थी ज़ुआन डुंग ने सीसीपी-कानून परियोजना का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया और इसके महत्वपूर्ण परिणामों पर प्रकाश डाला।
- कोवेंट्री विश्वविद्यालय के डॉ. मैथ्यू ब्लैकेट ने प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध पर एक प्रस्तुति दी।
- श्री होआंग थान हंग ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, इसके प्रभावों और इससे जुड़े जोखिमों पर अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण साझा किए तथा मूल्यवान अवधारणाएं प्रस्तुत कीं।
- सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉ. शशिकला गुरपुर ने अकादमिक पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन कानून और नीति को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया और बताया कि शिक्षा किस प्रकार सार्थक परिवर्तन ला सकती है।

सीसीपी-एलएडब्ल्यू अंतिम सम्मेलन के दूसरे सत्र में विचारोत्तेजक प्रस्तुतियों के साथ गति जारी रही, जिससे बातचीत गहन हुई और महत्वपूर्ण विषयों पर आकर्षक संवाद को प्रोत्साहन मिला।

संवादपत्र की विशेषताएँ

अंतिम सम्मेलन - ह्यू यूनिवर्सिटी, वियतनाम

अंतिम परियोजना संगोष्ठी -वियतनाम के ह्यू शहर मे

शीर्षक फोटो

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

सीसीपी कानून- 9वां सवांद पत्र

- गिरोना विश्वविद्यालय के डॉ. अल्बर्ट रुडा ने जलवायु क़ानूनी विवादों के भविष्य पर एक अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रस्तुति दी, जिसमें देखभाल के कर्तव्य से लेकर कॉर्पोरेट स्थिरता के लिए उचित परिश्रम तक के संक्रमण की जांच की गई।
- प्रोफेसर ले वान थांग ने जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वियतनाम की भागीदारी पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की।
- मारवाड़ी विश्वविद्यालय के डॉ. राहुल जे निकम ने जलवायु न्याय: वैश्विक स्थिरता चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी और पर्यावरणीय रास्ते पर एक व्यापक प्रस्तुति दी।

सम्मेलन में, प्रतिभागियों ने सीसीपी-कानून परियोजना के उद्देश्यों पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन नीति और कानून में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित करना, परीक्षण करना और समायोजित करना है, जो एक ऐसे शिक्षण दृष्टिकोण पर आधारित है जो सहजता और विविध शिक्षण उपकरणों के उपयोग को जोड़ता है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मलेशिया, भारत और वियतनाम में भागीदार भागीदारों के लिए आधुनिकीकरण, सुगमता बढ़ाने और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में योगदान देते हैं।

पाठ्यक्रम पूरा होने पर, शिक्षार्थियों को जलवायु परिवर्तन नीति और कानून में पेशेवर रूप से संलग्न होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त होंगे।इसके अतिरिक्त, एशिया के छह विश्वविद्यालयों में छह जलवायु परिवर्तन नीति और कानून केन्द्रों की स्थापना से प्रभावी अनुसंधान नेटवर्क कनेक्शन को बढ़ावा मिलेगा, संस्थागत पहलों के साथ संपर्क सुगम होगा, तथा पर्यावरण नीतियों और कानूनों के विकास और कार्यान्वयन को समर्थन मिलेगा।

अंतिम परियोजना संगोष्ठी -वियतनाम के ह्यू शहर मे

अंतिम परियोजना बैठक मुख्य प्रशिक्षण परिणामों और मुख्य प्रशिक्षण मूल्यांकन की गहन समीक्षा के साथ संपन्न हुई। परियोजना सदस्यों को नवीनतम परियोजना गतिविधियों के बारे में बातचीत करने और परियोजना के समापन की तैयारी करने का अवसर दिया गया।

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

परियोजना कार्यान्वयन के ४ वर्षों (२०२१-२०२५) के बाद सीसीपी-कानून परियोजना के संघ ने अपने संस्थानों में ६ स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक विकसित और प्रारम्भ किया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एशियाई भागीदार देशों की गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों के माध्यम से मान्यता प्राप्त है और ये यूरोपीय मानकों को पूरा करते हैं।

सीसीपी-कानून परियोजना सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिससे इसके प्रमुख उद्देश्यों और मील के पत्थरों की उपलब्धि का संकेत मिला। इस परियोजना ने बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है तथा नवोन्मेषी शिक्षा की स्थापना में योगदान दिया है, जो छात्रों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक कौशल से प्रवीण करेगी। इस परियोजना के परिणाम जलवायु परिवर्तन कानून के क्षेत्र में भविष्य की पहल और निरंतर प्रगति के लिए नींव का काम करेंगे।

शीर्षक फोटो